

अफगानस्तान से सुरक्षा संबंधी खतरा

प्रलिमिंस के लिये:

चाबहार पोर्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC), TAPI पाइपलाइन, UNSC, SCO, BRICS

मेन्स के लिये:

अफगानस्तान में तालबिन शासन की बहाली का भारत एवं वशिव पर प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने अफगानस्तान में तालबिन शासन की बहाली के बाद रूस और जर्मनी की सरकार के प्रमुखों के साथ संपर्क स्थापति कथि। अफगानस्तान में स्थरिता इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा से जुडी है और भारत इसका कोई अपवाद नहीं है।

- अफगानस्तान के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच मतभेदों तथा तालबिन को सुवधि प्रदान करने में पाकस्तान की भूमिका के बावजूद रूस ने **UNSC**, **SCO** एवं **BRICS** जैसे अन्य मंचों पर द्वपिक्षीय तथा बहुपक्षीय रूप से भारत के साथ काम करने में रुचि दिखाई है।





प्रमुख बडि

अफगानसितान में तालबान शासन की वापसी:

- वर्ष 2020 में अमेरिका ने तालबान के साथ (कतर की राजधानी दोहा में) एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसमें अफगानसितान से वदेशी सैनिकों की पूर्ण वापसी की परिकल्पना की गई थी।
- हालाँकि उस समझौते में प्रमुख दोष यह था कि इसमें अफगान सरकार को बाहर कर दिया गया था।
 - इसके अलावा वे तालबान लोकतांत्रिक सरकार को वैध शासक के रूप में नहीं देखते हैं और वे संविधान के शासन या लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं।
- इसलिये अमेरिकी सैनिकों की वापसी के तुरंत बाद तालबान ने अफगानसितान में राजधानी काबुल सहित प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया।
- इसने सीमा पार आतंकवाद, मानवीय संकट और नई भू-राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में विभिन्न चर्चाओं को उठाया है।

अफगानसितान से नषिकासति आतंकवादी भारत के लिये खतरा:

- **सीमा पार आतंकवाद:** भारत सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे से चर्चित है, जो अब तालबान शासन के वापस आने के बाद बढ़ सकता है।
 - लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूह, जो तालबान के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं और जिन्हें पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है, क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिये खतरा हैं।
- **धार्मिक कट्टरवाद:** सभी कट्टरपंथी समूहों की तरह तालबान को अपनी धार्मिक विचारधारा को राज्य के हितों की अनविद्यता के साथ संतुलित करने में परेशानी होगी।
- **नए क्षेत्रीय भू-राजनीतिक विकास:** चीन-पाकिस्तान-तालबान के बीच नई क्षेत्रीय भू-राजनीतिक धुरी का निर्माण हो सकता है, जो भारत के हितों के खिलाफ हो सकता है।
- **आर्थिक नुकसान:** तालबान के वापस आने से अफगानसितान में भारत का निवेश खतरे में पड़ जाएगा। यह अफगानसितान के माध्यम से मध्य एशिया के लिये कनेक्टिविटी परियोजनाओं को भी बाधित करेगा।
 - उदाहरण के लिये [चाबहार पोर्ट](#), [इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरडोर \(INSTC\)](#), [TAPI पाइपलाइन](#)।

अफगानसितान के साथ संबंधों में भारत की राजनयिक भागीदारी:

- हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ब्रिक्स देशों (ब्राज़ील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका) के [राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों](#) (NSAs) की बैठक की अध्यक्षता की।
 - इस बैठक में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन द्वारा वचिार हेतु ब्रिक्स काउंटर टेररज़िम एक्शन प्लान को अपनाने हेतु सफ़ारिश की गई।
 - कार्ययोजना का उद्देश्य नमिनलखिति क्षेत्रों में सहयोग के मौजूदा तंत्र को और अधिक मज़बूती प्रदान करना है:
 - आतंकवाद के वलित्तपोषण से नपिटना।
 - आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग पर अंकुश।
 - आतंकवादियों की यात्रा पर अंकुश।
 - सीमा नयितरण।
 - क्षमता नरिमाण।
 - क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग।
- [संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद](#) के 31वें वशिष सत्र में भारत द्वारा अफगानस्तान में गंभीर मानवाधिकार चतिाओं और स्थितिपर वभिन्न चतिाओं को उठाया गया।

आगे की राह:

- **तालबान के साथ बातचीत:** तालबान से बात करके भारत नरितर वक़ास सहायता के बदले वदिरोहयिों से अपनी सुरक्षा गारंटी की माँग कर सकता है।
 - भारत, तालबान को पाकस्तान से अपनी स्वायत्तता की संभावना तलाशने हेतु भी राजी कर सकता है।
- **वैश्विक आतंकवाद से लड़ना:** वैश्विक समुदाय को आतंकवाद की वैश्विक चतिा के खलिाफ लड़ने की ज़रूरत है।
 - इस संदर्भ में अब [‘अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक कन्वेंशन’](#) (1996 में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावित) को अपनाने का समय आ गया है।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** तालबान के पुनरुत्थान के साथ अफगानस्तान से एक राजनीतिक समझौते में भारत और तीन प्रमुख क्षेत्रीय देशों जनिमें चीन, रूस और ईरान शामिल हैं, के हति आपस में जुड़े हुए हैं।
 - इसलयि इस मोर्चे पर समान वचिारधारा वाले देशों से सहयोग की ज़रूरत है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/security-threats-emanating-from-afghanistan>

